

देवराज नागर,  
आई.पी.एस.



पुलिस महानिदेशक,  
उत्तर प्रदेश,

१-तिलक मार्ग, लखनऊ  
दिनांक:लखनऊःअक्टूबर १७, २०१३

**विषय-** जघन्य अपराधों जैसे हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार एवं डकैती आदि से सम्बन्धित साक्षियों के पक्षद्वाही (Hostile) होने की रोकथाम हेतु निर्देश।

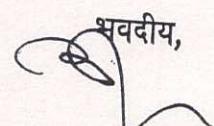
प्रिय महोदय/महोदया,

क्रिमिनल अपील संख्या: 3054/2013 उमेश यादव बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य जो मु०अ०सं० ६०५/२०११ धारा ३०२/२०१ भादंवि थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस के विषय में है। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में वादी श्री मलखान सिंह द्वारा अपनी पुत्री रीना की दहेज के कारण की गयी हत्या को लेकर धारा ३०४बी/४९८ए भादंवि एवं ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। मृतका रीना का शव नहर में पाया गया था, उसके गले पर चौट के निशान थे तथा मेडिकल परीक्षण से उसकी मृत्यु गला घोटने के फलस्वरूप होनी पायी गयी थी। विचारण के दौरान वादी सहित अधिकाशतः साक्षी पक्षद्वाही (Hostile) हो गये, परन्तु मा० न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अन्तर्गत सजा दी गयी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा उक्त अपील मा० उच्च न्यायालय में संस्थित की गयी। मा०उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक ०३.०९.२०१३ में गवाहों के पक्षद्वाही (Hostile) हो जाने के सम्बन्ध में असंतोष व्यक्त करते हुए गवाहों के पक्षद्वाही (Hostile) होने की रोकथाम हेतु निर्देश किये गये हैं।

2. अतः मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त निर्देशों का समावेश करते हुए जघन्य अपराधों (Hostile) होने की रोकथाम हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

- उपरोक्त जघन्य अपराधों की विवेचना में वैज्ञानिक विधियों का समावेश करते हुए विवेचना शीध्रतिशीध निस्तारित की जाये।
- क्रिमिनल लॉ (एमेण्डमेन्ट) एक्ट (२०१३) में हुए संशोधन के अनुसार बलात्कार के प्रत्येक प्रकरण में द०प्र०सं० की धारा १६१ के अन्तर्गत लिये जाने वाले पीड़िता के बयान की वीडियोग्राफी एवं १६४ द०प्र०सं० के अन्तर्गत मा० न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाना आवश्यक है। अतः उसका अक्षरशः पालन कराया जाय।
- हत्या, दहेज हत्या, डकैती तथा अन्य जघन्य अपराधों में जहों पर वादी एवं गवाहों के पक्षद्वाही होने की सम्भावना हो, वहों पर वादी एवं गवाहों की धारा १६१ द०प्र०सं० के अन्तर्गत लिये जाने वाले बयान की वीडियोग्राफी/ऑडियोग्राफी करायी जाय तथा १६४ द०प्र०सं० के अन्तर्गत मा० न्यायालय में कलमबन्द बयान कराया जाय ताकि वादी एवं गवाहों के पक्षद्वाही होने पर उनसे क्रास जिरह किया जा सके तथा उनके विस्तृत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सके।
- यदि वादी अथवा गवाहों को अभियुक्त पक्ष द्वारा डराया अथवा धमकाया जाता है तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाये तथा अभियुक्त पक्ष के विस्तृत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाये।

- न्यायालय में विचारण के दौरान यदि अधिकांश गवाह पक्षद्वारा ही हो रहे हों तो अभियुक्त/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की जाय, जिससे शेष गवाह पक्षद्वारा ही न हो सकें।
  - विचारण में अधिक समय लगने पर वादी की अभिखचि अभियुक्त को सजा दिलाने में कम हो जाती है। अतः विचारण के दौरान नियत तिथियों पर गवाहों को न्यायालय में उपस्थित कराया जाये, जिससे विचारण शीघ्र हो जाये और अभियुक्तगण को वादी एवं गवाहों को डराने, धमकाने एवं प्रलोभन देने का अवसर न मिले।
  - विचारण हेतु उपस्थित न होने वाले तथा फरार अभियुक्तों को प्रत्येक दशा में माझन्यायालय के समक्ष उपस्थित किये जाने हेतु कठोर व त्वरित कार्यवाही की जाये।
- अतः उपरोक्त सम्बन्ध में समुचित व त्वरित विधिक कार्यवाही की जाये एवं दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।



श्वदीय,  
(देवराज नागर) १२ - १० . १३

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),  
प्रभारी जनपद(नाम से)  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ०प्र० लखनऊ।
- 2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी०बी०सी०आई०डी०, उ०प्र० लखनऊ।
- 3.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
- 4.पुलिस महानीरीक्षक, समस्त जोन, उ०प्र०।
- 5.पुलिस उपमहानीरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ०प्र०।